भारत

मध्यम स्तरीय प्रगति

2024 में, भारत ने बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों को समाप्त करने के प्रयासों में मध्यम स्तरीय प्रगति की। रेलवे सुरक्षा बल, जिसने पिछले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक बच्चों को तस्करी वाली स्थितियों से निकाला है, एक संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया *(SOP)* शुरू की है जिसमें भारतीय रेलवे में बाल तस्करी को रोकने के लिए अधिक मज़बूत ढाँचे और संरचना की रूपरेखा दी गई है।तमिलनाडु में, सरकार ने 44,000 प्रतिष्ठानों में विशेष निरीक्षणों के माध्यम से 65 बच्चों सहित 330 से अधिक बंधुआ मज़दूरों को बचाया। इसके अतिरिक्त, सरकार ने बाल श्रमिकों को बचाने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिए एक महीने लंबा कार्यक्रम चलाया, जिसमें क्षेत्रीय निरीक्षण करना, जागरूकता कार्यक्रम चलाना और बच्चों को स्कूल कार्यक्रमों में नामांकित करना शामिल था। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, सरकार के वर्त्तमान निषिद्ध संकटपूर्ण कार्यों में वे सभी व्यवसाय शामिल नहीं हैं जिनमें बच्चे असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर वातावरण में काम करते हैं। बाल श्रम से संबंधित कार्यक्रमों और प्रणालियों का लागू करण तथा नीतियों का प्रवर्तन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक जैसा नहीं है। बाल तस्करी सहित बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों से संबंधित अपराधों के लिए मुक़दमा चलाने की दरें कम बनी हुई हैं, और पुलिस द्वारा बाल श्रम के मामलों का अनुचित ढंग से निपटारा करना चिंता का विषय बना हुआ है। विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के बढ़ाए गए लागूकरन के माध्यम से, सरकार ने बाल श्रम को संबोधित करने के लिए काम करने वाले संगठनों सहित, गैर-सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों के लाइसेंस रद्द करना जारी रखा।

बाल श्रम के लिए सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां

नीचे सुझाई गई सरकारी कार्यवाहियां उन कमियों को दूर करेंगी जिन्हें *USDOL* ने पहचाना है कि ये बाल मजदूरी के निकृष्टतम रूपों को समाप्त करने के लिए भारत द्वारा इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के लागूकरन में मौजूद हैं।

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही
क़ानूनी ढांचा	सभी क्षेत्रों में सभी बच्चों के लिए निषिद्ध खतरनाक कामों की सूची में ऐसे कार्यों को शामिल करें, जिसमें बच्चे असुरक्षित और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में काम करते हैं, जैसे कि कपड़ा और परिधान उत्पादन, कालीन निर्माण, और घरेलू काम।
	बाल तस्करी कानूनों में संशोधन करें ताकि उनमें बाल तस्करी के अपराध के लिए धमकियों, बल प्रयोग या दबाव की आवश्यकता न हो।
	वह क़ानूनी दस्तावेज़ प्रकाशित किया जाए जो भारत की सशस्त्र सेना में स्वैच्छिक भर्ती के लिए न्यूनतम आयु स्थापित करता है।
	सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को व्यावसायिक, सुरक्षा, स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति की संहिता को लागू करने के लिए नियम बनाने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि बच्चों को काम के खतरनाक रूपों से बचाया जा सके।
प्रवर्तन	लगभग 49.2 करोड़ लोगों के श्रम बल की पर्याप्त ढंग से निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 32,829 श्रम निरीक्षकों को नियुक्त करें, और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में श्रम निरीक्षकों को बाल मजदूरी पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करें।
	श्रम कानून प्रवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय आँकड़े वार्षिक रूप से प्रकाशित करें, जिसमें श्रम निरीक्षकों की संख्या, श्रम निरीक्षणालय के वित्तपोषण, और कार्यस्थल पर तथा बिना पूर्व सूचना के किए गए निरीक्षणों की संख्या जुड़े आंकड़े शामिल हों।
	आपराधिक जाँचकर्ताओं, अभियोजकों और न्यायाधीशों को बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और पर्याप्त संसाधन प्रदान करें, जिनमें शामिल हैं: सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपराधिक जाँचकर्ताओं को बंधुआ श्रम (उन्मूलन) अधिनियम सहित बाल श्रम से संबंधित कानूनों पर पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करना; राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मानव तस्करी विरोधी इकाइयाँ स्थापित करने के लिए समर्पित वित्त-पोषण कर्मचारी, और बुनियादी ढाँचा प्रदान करना; यौन अपराधों से पीड़ित बच्चों के लिए सुचारु सुनवाई प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु असुरक्षित गवाह बयान केंद्र स्थापित करना; और यह सुनिश्चित करना कि न्यायाधीशों और अभियोजकों को बाल यौन अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित किया जाए।

क्षेत्र	सुझाई गई कार्यवाही
	बाल श्रम अपराधों के निकृष्टतम रूपों से संबंधित जाँच-पड़तालों, दोषसिद्धियों और अभियोजनों की संख्या सहित, आपराधिक कानून प्रवर्तन से संबंधित राष्ट्रीय आँकड़े वार्षिक आधार पर प्रकाशित करें।
	सुनिश्चित करें कि आपराधिक कानून एजेंसियाँ बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों से संबंधित अपराधों का उचित रूप से पता लगाएँ, उनकी जाँच-पड़ताल करें, उन पर मुकदमा चलाएँ और दंडित करें, जिनमें शामिल हैं: बंधुआ श्रम के मामलों में तेजी लाकर और श्रम शोषण के अपराधियों पर लगातार मुकदमा चलाकर बंधुआ श्रम प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम को पर्याप्त रूप से लागू करना; यह सुनिश्चित करना कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत सभी मामले शीघ्र निपटारा विशेष न्यायालयों में अभियोजन के लिए निर्धारित 1 वर्ष की समय-सीमा का पालन करें; यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लंबित मामलों का निपटारा करना; और निम्न जातियों की लड़कियों को मंदिर संरक्षकों द्वारा वस्तुगत भुगतान या नकद भत्ते के बदले में यौन शोषण का शिकार होने से बचाने के लिए जोगिनी प्रथा के अपराधियों पर मुकदमा चलाना और उन्हें जवाबदेह ठहराना।
	ऐसे सार्वजनिक अधिकारियों को जवाबदेह ठहराएं जो बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों में सहायता करते हैं, उनमें भाग लेते हैं या उनसे निपटने के प्रयासों बाधा डालते हैं, जिनमें वे अधिकारी शामिल हैं जो रिश्वत स्वीकार करते हैं, बच्चों को कृषि में और ईंट भट्टों में बंधुआ श्रम में रखते हैं, और जो मानव तस्करी के मामलों को दर्ज करने में देरी करते हैं या मानव तस्करी से बच कर निकले लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
तालमेल	बाल मजदूरी अधिनियम को लागू करने के लिए कार्यदल द्वारा और बाल एवं किशोर मजदूरी पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा बाल मजदूरी को संबोधित करने और रोकने के लिए की गई गतिविधियों को वार्षिक रूप से प्रकाशित करें।
सरकारी नीतियां	सुनिश्चित करें कि बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना, और बाल श्रम पर राज्य कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए गतिविधियाँ की जाती हैं और इन योजनाओं को लागू करने के लिए की गई गतिविधियों के परिणाम वार्षिक आधार पर प्रकाशित किए जाते हैं।
	जिन राज्यों और क्षेत्रों के पास वर्तमान में बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए कार्य योजना नहीं है उन्हें ऐसी योजनाओं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें।
सामाजिक कार्यक्रम	शिक्षकों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करके, लड़कियों के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय प्रदान करके और उपलब्ध स्कूलों की संख्या बढ़ाकर, विशेष रूप से शहरी मलिन बस्तियों में, जहाँ अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे के विकल्प शिक्षा तक पहुँच को सीमित करते हैं, निम्न जातियों, जनजातीय समुदायों के सदस्यों और धार्मिक अल्पसंख्यकों सहित सभी बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुँच को बढ़ावा दें और बाधाओं को कम करें।
	हर राज्य में शोषणकारी बाल मजदूरी पर केन्द्रीय आंकड़े संग्रह के माध्यम से आंकड़े एकत्र करें और जनता के लिए उपलब्ध कराएँ, जिसमें जिला-स्तरीय बंधुआ श्रम सर्वेक्षणों के निष्कर्ष और राष्ट्रीय जनगणना के कच्चे आंकड़े शामिल हैं।
	सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारें बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना के माध्यम से बंधुआ श्रम से मुक्त होने वालों के लिए पूर्ण प्रतिकर सहित, बंधुआ श्रमिक पीड़ितों के लिए मुक्ति प्रमाण पत्र जारी करें और वित्तीय सहायता प्रदान करें।
	बाल श्रमिकों को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों सहित शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तपोषण प्रदान करें, और सभी राज्यों और क्षेत्रों में पुनःप्रवेश कार्यक्रम और देखभाल के बाद की सेवाएं प्रदान करें।
	सुनिश्चित करें कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम का उपयोग बाल मजदूरी-केंद्रित गैर-सरकारी संगठनों *(NGOs)* को अंतर्राष्ट्रीय धन प्राप्त करने या देश में काम करने के लिए उनके लाइसेंस को बनाए रखने से रोकने के लिए नहीं किया जाता है।
	सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को समय पर और सुसंगत ढंग से मानव तस्करी आश्रयों के लिए धन उपलब्ध कराएं।
	धार्मिक अल्पसंख्यकों, निम्न जाति के बच्चों तथा बांग्लादेश और नेपाल के बच्चों सहित भारत में कमजोर आबादी के बीच बाल श्रम, बंधुआ बाल श्रम और बाल तस्करी को संबोधित करने के लिए सामाजिक कार्यक्रम विकसित और लागू करें।